







# विचार

# क्या नया वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी है?

बीते हफ्ते संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक ( यू.एम.ई.डी.डी. ), 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद कानून बन गया। राजनीतिक कारणों ( वोट बैंक सहित ) से विपक्षी दलों के निजी स्वार्थ के चलते कई इस्लामी संगठनों का आरोप है कि नया वक्फ कानून 'मुस्लिम विरोधी' और 'संविधान के खिलाफ' है। इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 10 से अधिक याचिकाएं दायर हुई हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 7 अप्रैल को सत्तारूढ़ नैशनल कांफैंस के एक विधायक ने सदन में इस नए कानून की प्रति फाड़कर अपना रोष जाहिर किया, तो मणिपुर में इसका समर्थन करने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के घर को अराजक तत्वों ने फूंक दिया। यह स्थिति तब है, जब इसके विरोध को लैकर मुस्लिम समाज ही बंटा हुआ है। यह ठीक है कि नए वक्फ कानून के संवैधानिक, न्यायिक पक्ष का फैसला अदालत में होगा। परंतु इसके अन्य पक्ष भी हैं, जिस पर ईमानदारी से विचार करना चाहिए।

क्या वक्फ जैसा कानून भारत में किसी और अल्पसंख्यक समूह, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी आदि के लिए है? हिंदू और सिख ट्रस्ट जहाँ सरकारी निगरानी में काम करते हैं, वहीं वक्फ बोर्ड पर कोई नियंत्रण नहीं था, जिससे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को बढ़ावा मिला। नया वक्फ कानून इस स्थिति को सुधारता है और कानूनी प्रक्रिया को बल देता है। वक्फ का अर्थ किसी चल-अचल संपत्ति को स्थायी तौर पर उन कार्यों के लिए दान करना है, जिन्हें इस्लाम में पवित्र और मजहबी माना जाता है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार, अल्लाह ही वक्फ संपत्तियों के मालिक हैं, लेकिन उनका भौतिक प्रबंधन मुतवली और देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड करते हैं। वर्ष 1954 से लेकर वक्फ संपत्तियों के नियंत्रण, कानूनी अड़चन और बेहतर प्रबंधन आदि को लेकर वक्फ अधिनियम में पहले से कई संशोधन हो चुके हैं।

देश में वक्फ का कामकाज पहले 'वक्फ अधिनियम, 1995' की छत्रछाया में होता था। इसे तब केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस नीत नरसिंहा राव सरकार ने कार सेवकों द्वारा 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में औपनिवेशिक बाबरी ढांचा ध्वस्त करने से छिटके मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने हेतु, 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले संशोधित किया था। इसका वांछित लाभ कांग्रेस को नहीं मिला और वह सत्ता से दूर रही। जब केंद्र में कांग्रेस नीत यू.पी.ए. सरकार (2004-14) रही तब उसने विभाजनकारी राजनीति के तहत देश में आए दिन होते इस्लामी आतंकवादी हमले के बीच फर्जी 'हिंदू भगवा आतंकवाद' जुमला गढ़ा और फिर मुस्लिम वौट बैंक को एकजुट रखने के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव से 6 माह पहले वक्फ अधिनियम (1995) में फिर से संशोधन करके मुस्लिम समाज को वह अधिकार दे दिया

# ट्रम्प डालर के जरिए दुनिया के राजनीतिक ढंगे को बदलना चाहते हैं



निकाल तो लिए पर लगाए कहाँ, फिर वही डालर। हाथी कितना भी पतला हो जाए, हाथी तो हाथी है। एक दिन के अंदर अमरीका के ब्याज की दर 4 अप्रैल को 4.16 प्रतिशत से घट कर 3.97 प्रतिशत रह गई। अब अगर यह ब्याज की दर 10 साल के बांड पर घट कर 2.5 प्रतिशत रह जाए तो अमरीका को हर साल 360 बिलियन डालर से

# वर्तमान वैश्विक पतल पर भारत के लिए आपदा में अवसर हैं

अमेरिका ने अन्य देशों से अमेरिका में होने वाली आयातित उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर विश्व के लगभग समस्त देशों के विरुद्ध एक तरह से व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। इससे यह आभास हो रहा है आगे आने वाले समय में विभिन्न देशों के बीच सापेक्ष युद्ध न होकर व्यापार युद्ध होने लगेगा। चीन से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर तो अमेरिका ने 145 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है। एक तरह से अमेरिका की ओर से चीन को यह खुली चुनौती है कि अब अपने उत्पादों को अमेरिका में निर्यात कर के बताए। 145 प्रतिशत के आयात कर पर कौन सा देश अमेरिका को अपने उत्पादों का निर्यात कर पाएगा, यह लगभग असभव है। इससे चीन की अर्थव्यस्था छिन्न भिन्न हो सकती है, यदि चीन, अमेरिका के स्थान पर विश्व के अन्य देशों को अपने उत्पादों का निर्यात नहीं बढ़ा पाया।



बगैर प्रत्यक्ष युद्ध किए, अमेरिका ने चीन पर एक तरह से विजय ही प्राप्त कर ली है और चीन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान करने के रास्ते खोल दिए हैं, हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी विपरीत रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। परंतु, ट्रम्प प्रशासन ने विश्व के 75 देशों पर लागू किए गए टैरिफ़ को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर अन्यथा होने वाले विपरीत प्रभाव को बहुत बड़ी हद तक कम कर लिए गया है। अमेरिका संभवत चाहता है कि आर्थिक मोर्चे पर चीन पर इतना दबाव बढ़ाया जाए कि चीन की जनता चीन के वर्तमान सत्ताधरियों के विरुद्ध उठ खड़ी हो और चीन एक तरह से टूट जाए। अमेरिका ने लगभग इसी प्रकार का दबाव बनाकर सोवियत रूस को भी तोड़ दिया था। कुल मिलाकर पूरे विश्व में विभिन्न देशों के बीच अब नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूरोपीयन यूनियन के समस्त सदस्य देश आपस में मिलकर अब अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहते हैं। अभी तक ये देश अमेरिका के सखा देश होने के चलते अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहते थे। परंतु, वैश्विक स्तर पर बदली हुई परिस्थितियों के बीच इन देशों का अमेरिका पर विश्वास कम हुआ है एवं यह देश आपस में मिलकर अपनी स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। आगे आने वाले समय में यूरोपीयन यूनियन के समस्त देश अपने सुरक्षा बजट में भारी भरकम वृद्धि कर सकते हैं। यहां, भारत के लिए अवसर निर्मित हो सकते हैं क्योंकि भारत में हाल ही के समय में सुरक्षा के क्षेत्र में उत्पादों की नई एवं भारी मात्रा में उत्पादन क्षमता निर्मित हुई है। भारत आज सुरक्षा के क्षेत्र में तेजी से न केवल आत्म निर्भर हो रहा है बल्कि भारी मात्रा में उत्पादों का निर्यात भी करने लगा है। आज सिंगापुर जैसे विकसित देश भी भारत से सुरक्षा उत्पाद खरीदने हेतु करार करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि यूरोपीयन देशों के साथ भारत की पटरी ठीक बैठ जाती है तो सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए अपार सम्भावनाएँ मौजूद हैं। भारत, यूरोपीयन देशों के साथ सामूहिक तौर पर द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने के प्रयास भी कर रहा है।

में उलझे रहते हैं, ट्रम्प डालर को एक विध्वंसा  
पति बनी ताक दर्शाया ताक चौके हैं।

शाक का तरह इस्तमाल कर रहे हैं। ट्रम्प के समीकरण में उनके टैरिफ़ का जब दुनिया देगी भी तो कैसे? हथियार के अल अमरीका दुनिया को बेचता ही क्या खास है दुनिया टैरिफ़ के बदले टैरिफ़ ठोके यूरोपियन यूनियन को साल का 240 बिलियन डालर्स का अमरीका से व्यापार में फायदा पहुंच है। क्या इसको गवाने का साहस उनमें वियतनाम ने पिछले साल 123 बिलियन डाल अमरीका से कमाए थे। जानते हैं कि 46 प्रतिशत टैरिफ़ पर उनका क्या जवाब है? कहते हैं माई-बाप हम अपना टैरिफ़ शून्य कर लौंगे ऐ ने कहा है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें 34 प्रतिशत टैरिफ़ का जवाब 34 प्रतिशत टैरिफ़ ट्रम्प के पहले शासनकाल में चीन पर 25 प्रतिशत का टैरिफ़ लगा था। चीन ने तब भी ईंट जवाब पत्थर से ही दिया था। पर अमरीका अर्थव्यवस्था पर एक प्वाइंट से भी कम नुकसान हुआ था। अमरीका को खरोंच तक न आई थी। पूरी दुनिया का पूरा व्यापार कुल मिकर 33 ट्रिलियन डालर्स है। इसका करीब प्रतिशत (5.4 ट्रिलियन डालर्स) अमरीका से है। दुनिया का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा ४ डालर्स में होता है। परी दुनिया का कर्ज 3

इन देशों को सुरक्षा का कवच मिलता है। फिर भी अगर उलझोगे तो अमरीका के सैंक्षण्स से कैसे निपटोगे। टैरिफ बिसात पर सिर्फ पहली चाल = पर ट्रम्प के लिए टैरिफ सिर्फ पहली चाल है। 50 देशों ने तो वैसे ही घुटने टेक दिए हैं। यह संख्या बढ़ायी जी। दो मूलता है कि कल तेज़ दात्य व्हाइटने

बढ़ाया है। हो सकता है कि कुछ दश डालर छाड़ानु की हिम्मत जुटा लें। हो सकता है कई देश चीन की युआन करंसी में ही धंधा करें। परं जिस तरह साइकिल के पहिए में एक भुरी होती है और कई तारें, अगर एक-दो तारें टूट भी जाएं, पहिए का चलना बांद नहीं हो जाता। फिर जो तारें टूट जाएंगी, उनसे टैरिफ से तो पैसा आएगा ही। ट्रम्प इन अलग-अलग तारों से अलग-अलग निपटेंगे। कुछ से कहेंगे कि हमारे बांडों की मैच्योरिटी बढ़ा कर 50 साल कर दो, ब्याज की दर कम होगी। कुछ से कहेंगे कि अपने सैंट्रल बैंक में जो डालर का अम्बार लगा कर बैठे हो उसे हल्का करो। पाबंदी होगी कि तुम धंधा डालर में ही करोगे। ज्ञानी कहते हैं कि राजनीति-वाजीनीति में उलझना समय की बर्बादी है। पैसे की चाल देखो खेल खुद समझ में आ जाएगा। ट्रम्प भी डालर के पासे से दुनिया के राजनीतिक ढांचे को अपनी सोच में ढालना चाह रहे हैं। उनकी सोच रूस से हाथ मिलाने की है। यूरोप को वह एक ऐसे शब्द की तरह मानते हैं जो उन्हें कंधे पर

दोना पड़ रहा है।  
ट्रम्प लगता है मान चुके हैं कि दुनिया दो-तीन  
खेमों में बंट सकती है। कुछ चीन के दरबार में जा  
बैठेंगे। यूरोप अपना एक अलग खेमा शायद बना  
ले। पर जब तक डालर में धंधा है, कर्ज है, सारी  
सप्लाई चेन है दुनिया के हर समुद्र के हर कोने में  
अमरीकी मिलिट्री बेस हैं तब तक हाथी सवा सेर  
का ही गड़गो।-







